dents are facing a lot of difficulties; if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes.

(b) 82 numbers (from 1st August to 27th November, 1987).

(c) and (d) The number of complaints remaining unattended to as on 8-12-87 is 36. The work has been given on contract and the contractor has completed the work only in one pocket, covering 46 complaints. He is being asked to restart the work by 10-12-87 and in case of his failure, the work will be got done through another agency. The entire pending work is likely to be completed by 15-1-1988.

भारत खाद्य निगम द्वारा भारतीय बीज निगम को गेहूं की पूर्ति किया जाना

3761. श्री शिव कुमार मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985–86, 1986–87 और 1987–88 के वर्षो के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय बीज निगम को कितनी मात्रा में गेहूं दिया गया है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय बीज निगम को किस मूल्य पर गेहूं दिया था और भारतीय बीज निगम ने उक्त गेहूं भारतीय किसानो को किस मूल्य पर बेचा था ;

(ग) भारतीय बीज निगम की प्रति बोरी लागत कितनी थी और इसने प्रति बोरी कितना लाभ अर्जित किया ; और

(घ) क्या भारतीय बीज निगम ने फसल की उन्नत उपज प्राप्त करने के लिए वास्तुत: बीज को उचित ढंग से संसाधित किया था ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) 1987–88 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं के दानो की 4.28 लाख क्विंटल मात्रा की अधिप्राप्ति की गई थी, जिनका परिसस्करण किए जाने के पश्चात् बीज के रूप में उपयोग किया जाना था। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1985–86 तथा 1986–87 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की किसी भी मात्रा की अधिप्राप्ति नही की गई।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम को 4 प्रतिशत बिक्री कर सहित 281.56 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय बीज निगम ने किसानों को गेहू के बीजो की सीधी बिक्री नही की। ये बीज बिहार और जम्मू काश्मीर राज्य को राज्यो में लागू लेवी तथा करो सहित 325/– रुपए प्रति क्विंटल की दर से सप्लाई किए गए हैं।

(ग) परिष्कृत तथा बोरा-बंद बीजो की एफ० ओ० आर० डिलीवरी केन्द्रो तक लागत 428.74 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है। राज्य सरकारो को बीजो की आपूर्ति 325 रुपए प्रति क्विंटल के सहाय्य मूल्य पर की गई है। भारत सरकार ने 103.74 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राजसहायता दी है। राष्ट्रीय बीज निगम को प्रचालन की कुल लागत का 3 प्रतिशत सेवा-प्रभार के रूप में प्राप्त होगा।

(घ) भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्त अनाज की राज्य सरकारो को आपूर्ति किए जाने से पूर्व इसे राष्ट्रीय बीज निगम, पंजाब राज्य बीज निगम, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम तथा बिहार राज्य बीज निगम के परिसंस्करण संयंत्रो मे उपयुक्त ढंग से परिष्कृत किया गया है।

Modern rice mills of the FCI

3762. SHRI ASHOK NATH VERMA: the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the modern rice mills of the Food Corpo-

mation of India lying idle for quite some time;

(b) if so, when those were established and the date from which those are lying idle and the expenditure incurred thereon; year-wise;

(c) whether it is also a fact that one divsion headed by Chief Engineer (Rice Mills) is still working in the Department of Food;

(d) if so, the number of persons category-wise in the Rice Mills Division and the expenditure incurred category-wise during the last three years; and

(e) the number of persons still working in the F.C.I. on this account and the expenditure incurred (category-wise)?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Fourteen of the twenty five Modern Rice Mills owned by the FCI have become economically non-viable and are not functioning regularly.

(b) A statement giving the required, information is attached. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 156]

(c) Yes, Sir.

(d) There are 4 group A, 2 group B and 3 group-C officials working in the Rice mills Division of the Department of Food. The expenditure incurred on account of salary and other allowances during the last 3 years is Rs. 9.20 lahs.

(e) 297 employees, comprising 14 category-II, 105 category-III and 178 category-IV, are still working in the fourteen uneconomic rice mills. The expenditure towards their salary for the period from 1985-86 to 1987-88 is about Rs. 40.40 lakhs.

Creation of additional capacity of milk

3763. SHRI VIRENDRA VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in March, 1987 an additional capacity of 50.54 lakh litres per day (LLPD) of milk was created under Operation Flood when during the year 1986-87 the annual average milk procurement was only 78.94 lakh litres per day for all Operation Flood milksheds whereas the rural dairy processing capacity alone was 117.45 LLPD,

(b) whether it is also a fact that the Jha Committee had recommended that Operation Flood resources should not be freely used in building up dairy plants in the country; and

(c) if so, what are the reasons for creating an additional capacity of 50.54 LLPD of milk in 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) The rural milk processing capacity during 1986-87 was of the order of 122.04 lakh litres per day (LLPD) as against 108.83 LLPD during 1985-86.

Milk processing capacities are created to meet the peak milk procurement in the future years.

पटौदी हाउस, नई दिल्ली का गिराया जाना

3764. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कनाट प्लेस, नई दिल्ली के निकट स्थित पटौदी हाउस से बहुमूल्य फर्नीचर तथा साज-सामान की चोरी होने के बारे में जानकारी है ;